आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 11.03.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया – घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की कमी नहीं। तेल कंपनियों ने एलपीजी उत्पादन बढ़ाया।
- भराड़ीसैंण में राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक, 11 विधेयक सदन में पेश किए गए।
- केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 264 करोड़ रुपये से अधिक की विशेष सहायता स्वीकृत की।
- बदरीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति की बैठक में 121 करोड़ से अधिक का अनुमानित बजट पारित।

सरकार / ईंधन

केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कोई कमी नहीं है और घबराने की कोई वजह नहीं है। सरकार देश के घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत का ऊर्जा आयात विभिन्न स्रोतों और मार्गों से लगातार जारी है।

एलपीजी उत्पादन

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल और भारत पेट्रोलियम ने कहा है कि एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं तथा अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक जगहों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, ऑयल कंपनियों ने कहा है कि अन्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों की समीक्षा तेल विपणन कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक समिति द्वारा की जाएगी। ऐसे अनुरोधों को उनकी योग्यता, आवश्यकता और एलपीजी की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।

बजट सत्र

भराड़ीसैंण में राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान 11 विधेयक सदन में पेश किए गए, जबकि चार अध्यादेश पटल पर रखे गए। प्रश्नकाल में सदस्यों ने वन मंत्री सुबोध उनियाल और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के विभागों से जुड़े प्रश्न उठाए। विपक्षी सदस्यों के सवालों के बीच दोनों मंत्रियों को कई बार असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। प्रश्नकाल के बाद पूर्व विधायक दिवाकर भट्ट, बलवीर सिंह नेगी और राजेश जुआंठा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भोजनावकाश के बाद कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनके नोटिस नियम 310 के तहत स्वीकार नहीं किए गए। कांग्रेस सदस्यों ने पीठ पर सत्ता पक्ष के दबाव में कार्य करने का आरोप लगाया, जिस पर सदन में काफी देर तक शोर–शराबा हुआ।

पिरूल

प्रदेश सरकार ने राज्य में वनाग्नि को रोकने के लिए गंभीर प्रयास शुरू किए हैं। इसके तहत वन विभाग के माध्यम से एक वर्ष के भीतर ग्रामीणों से पांच करोड़ 42 लाख रूपये का पिरूल खरीदा है। चीड़ के जंगलों में आग लगने के मूल कारण को खत्म करने के लिए ग्रामीणों से पिछले साल 5 हजार 532 टन पिरूल खरीदा गया है। इस लक्ष्य को अब बढ़ाकर 8 हजार 555 टन कर दिया गया है। बजट सत्र के दूसरे दिन कल प्रश्नकाल में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने यह जानकारी साझा कीं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि पिरुल एकत्रित कर वनाग्नि की आशंका को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा दिया जाए। उन्होंने बताया कि वनाग्नि को रोकने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों में जन–जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक हजार 239 जागरूकता शिविर लगाए गए हैं। वन मंत्री ने बताया कि सरकार ने सबसे अहम काम यह किया है कि ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में वनाग्नि प्रबंधन समिति गठित की है, जो विभाग के साथ मिलकर जंगल बचाने में जुट रही हैं। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत को 30 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि वनाग्नि के दौरान फायर वॉचर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए धामी सरकार ने पहली बार बीमे का सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया है। फायर वॉचर्स का दस लाख रुपए का सामूहिक बीमा किया गया है। श्री उनियाल ने बताया कि पिछले वर्ष वनाग्नि रोकने में पांच हजार 600 फायर वाचर्स ने अपना योगदान दिया था।

वित्तीय सहायता

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को शहरी भूमि एवं नियोजन सुधारों को बढ़ावा देने के लिए 264 करोड़ 50 लाख रुपए की विशेष सहायता स्वीकृत की है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत यह राशि राज्य में प्रस्तावित विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई है, जिससे

शहरी विकास, भूमि प्रबंधन और नियोजन सुधारों को गति मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा यह पूरी राशि एकमुश्त किस्त में राज्य को जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह वित्तीय सहायता, उत्तराखंड में योजनाबद्ध शहरी विकास, आधुनिक भूमि प्रबंधन प्रणाली और मजबूत आधारभूत ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में बेहतर नियोजन, सुव्यवस्थित विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस सहायता से प्रदेश के शहरों में संतुलित और टिकाऊ विकास को गति मिलेगी तथा आम नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

अग्निवीर संवाद

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में अग्निवीर सैनिकों के रूप में भर्ती होने वाले कैडेट्स के साथ संवाद किया। इस दौरान कैडेट्स ने मुख्यमंत्री से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका मुख्यमंत्री ने सहजता से उत्तर दिया। इस अवसर पर अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना तेजी से आत्मनिर्भर बन रही है।

बीकेटीसी

बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति– बीकेटीसी की देहरादून में हुई बैठक में आगामी यात्रा सत्र 2026–27 को दृष्टिगत रखते हुए 121 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमानित बजट पारित किया गया। साथ ही बदरीनाथ और केदारनाथ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने सहित कई अहम प्रस्तावों को भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बीकेटीसी का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सरल– और सुगम दर्शन व्यवस्था करना है। इसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। गौरतलब है कि 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही प्रदेश में इस वर्ष चारधाम यात्रा शुरु हो जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को और बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर–

केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस के उपयोग की प्राथमिकताओं को फिर से तय कर दिया है। यह ख़बर आज के सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। दैनिक जागरण का शीर्षक है– घरों और परिवहन क्षेत्र को मिलेगी पूरी गैस। आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू, जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बनाई निगरानी समिति।

गैरसैंण में आयोजित राज्य विधानसभा के बजट सत्र की ख़बर भी सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। दूसरे दिन सदन में चार अध्यादेश व ग्यारह विधेयक पेश, विपक्ष का हंगामा। इस सुर्खी के साथ अमर उजाला लिखता है– विधानसभा अध्यक्ष व विपक्ष में बहस, विपक्ष ने लगाया सरकार पर दबाव में सदन चलाने का आरोप। कार्यवाही पांच बार स्थगित, वेल में प्रदर्शन।

एक अन्य ख़बर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है– उत्तराखंड में धुंध के कारण इक्तीस हेली उड़ानें रद्द। विजिबिलिटी कम होने से उड़ान नहीं भर सके हेलीकॉप्टर, मौसम बदलने से धुंध बढ़ी, लोगों ने झेली परेशानी। समाचार पत्र, राज्य मौसम विभाग के निदेशक डॉ. सी.एस तोमर के हवाले से यह भी लिखता है कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और आने वाले दिनों में चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी जैसे पर्वतीय ज़िलों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है।